

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 43/2018 राजस्व अपील

1. शिम्भूलाल पुत्र मीठालाल गुर्जर जाति गुर्जर निवासी पीपलकी तहसील सिकराय उप तहसील सिकन्दरा जिला दौसा

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार सिकन्दरा जिला दौसा

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध नायब तहसीलदार सिकन्दरा निर्णय दिनांक 24.09.2015

उनवानी प्रकरण सरकार बनाम शिम्भूलाल मु.न. 296/2015

अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम

उपस्थिति : श्री विश्राम गुर्जर अधिवक्ता अपीलान्ट उप0।

: श्री चन्द्रशेखर टापरिया राजकीय अधिवक्ता उप0।

—: निर्णय :—

दिनांक: 13.06.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि पटवारी हल्का पीपलकी द्वारा अपीलान्ट के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट ने ग्राम पीपलकी तहसील सिकराय में स्थित भूमि खसरा नम्बर 43/1 रकबा 1.10 बीघा किस्म चरागाह पर संवत् 2072 में बाजरा की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल किये जाने एवं 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से भी दिनांक 24.09.2015 को दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 24.09.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की

गई है।

अति० जिला कलक्टर

दौसा



प्रकरण संख्या : 43/2018 राजस्व अपील

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोंडेंट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्त ने सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को कोई सुनवाई व सबूत का मौका नहीं दिया ना ही पटवारी हल्का ने अपीलान्त के समक्ष भूमि का मौका देखा ना मौका रिपोर्ट बनाई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की झूठी व बेबुनियाद रिपोर्ट को सही मानकर अपीलान्त को प्रश्नगत आराजी भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए दिनांक 24.09.2015 को निर्णय पारित कर दिया। अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी साबित नहीं है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्त अतिक्रमी द्वारा ग्राम पीपलकी तहसील सिकराय में स्थित भूमि खसरा नम्बर 43/1 रकबा 1.10 बीघा किस्म चरागाह पर संवत् 2072 में बाजरा की काश्त कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्त अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 24.09.2015 के द्वारा अपीलान्त अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करने एवं 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 60 दिन का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है, किन्तु अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा बहस के



असि० जिला कलेक्टर
जहानाबाद

प्रकरण संख्या : 43 / 2018 राजस्व अपील

दौरान निवेदन किया गया की अपीलान्ट का प्रश्नगत चरागाह भूमि पर अतिक्रमण नहीं है तथा भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जावेगा। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम पीपलकी तहसील सिकराय मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 43/1 रकबा 1.10 बीघा किस्म चरागाह पर से अतिक्रमण हटा लिया जाने एवं भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ पत्र नायब तहसीलदार सिकन्दरा के समक्ष प्रस्तुत करने एवं नायब तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा अतिक्रमण हटा लिया जाना सत्यापित किया जाने पर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.09.2015 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
दौसा

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
दौसा